मुजेसर डिस्पेंसरी : आयुर्वेदिक डॉक्टर करता है एलोपैथिक इलाज

नकली चेहरा : तीन मंजिला डिस्पैंसरी

असली चेहरा : सड़ता मैडिकल वेस्ट

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकार की चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की आम जनता को इलाज के नाम पर यूं मूर्ख बनाने का काम होता रहेगा। शहर के बीचो बीच स्थित मुजेसर गांव की डिस्पेंसरी में सरकार गरीब तबके का इलाज करने के नाम पर सिर्फ खानपूर्ति कर रही है।

डिस्पेंसरी के भवन का निर्माण कांग्रेस के शासनकाल में वर्ष 2012 में पूरा करने के बाद इसकी शुरूआत की गई थी लेकिन मात्र पांच साल गुजरने के बाद ही यह भवन जर्जर होना शुरू हो गया है। भवन की हालत को देख कर स्पष्ट नजर आता है कि इसके निर्माण कार्य में तत्कालीन सत्ताधारी नेताओं ने ठेकेदार से मिलकर घपला किया है। भवन का जगह जगह से पलस्तर झड़ने के साथ साथ इसमें जगह जगह दरारे आनी शुरू हो गई। इस स्थिति के कारण भवन के भूतल और प्रथम तल का इस्तेमाल ही डिस्पेंसरी के काम के लिए किया जा रहा है। देखरेख के अभाव में भवन के ज्यादातर शीशे टूटे चुके है।

हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे करने वाली प्रदेश की खट्टर सरकार इस डिस्पेंसरी में अन्य सुविधाएं जुटाना तो दूर यहां डॉक्टर तक नहीं जुटा पा रही है। डिस्पेंसरी में अनुबंध के आधार एक एमबीबीएस महिला डॉक्टर और एक आर्युवैदिक डॉक्टर मौजूद है। अस्पताल की प्रभारी डॉ. नीरू गुप्ता सिर्फ महिला संबंधित रोगों का इलाज करती है। जबकि अन्य मरीजों का इलाज आर्युवैदिक डॉक्टर सीमरजीत सिंह एलोपैथिक दवाईयों से करते है। डिस्पेंसरी को आर्युवैदिक दवाईयां कभी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। एलोपैथिक दवाईयां आती भी है तो आधी अधूरी। दो डॉक्टरों के अलावा डिस्पेंसर में पांच स्टाफ नर्स, दो एएनएम, दो लैब तकनीशियन और दो फार्मासिस्ट तैनात हैं। इनमें एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी फिलहाल बीके अस्पताल के सेन्ट्रल स्टोर में चल रही है। डिस्पेंसरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पद समाप्त कर दिए गए हैं।

फिलहाल डिस्पेंसरी में साफ सफाई करने के लिए एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी रखा गया है। जो सुबह सुबह भूतल की साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर चला जाता है। जिसके कारण डिस्पेंसरी परिसर में चारों तरफ गंदगी भरा माहौल बना रहता है। ऐसे में मुजेसर गांव के स्थानीय लोग इस डिस्पेंसरी में आने से कतराते हैं।

डिस्पेंसरी से हर रोज निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को उठाने की कोई व्यवस्था जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज तक नहीं की गई है। डिस्पेंसरी से हर रोज भारी मात्रा में मेडिकल वेस्ट निकलता है। जिसे कर्मचारी इक्ट्ठा करने के बाद डिस्पेंसरी के पीछे ले जाकर जला देते है। बाकी अधजला मेडिकल वेस्ट डिस्पेंसरी परिसर में इधर उधर बिखरा हुआ कभी भी देखा जा सकता है। जिससे डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों और आसपास रहने वाले लोगों की जान का खतरा बना रहता है।

कहने को डिस्पेंसरी में प्रयोगशाला और लैब तकनीशियन मौजूद है। लेकिन इस प्रयोगशाला में किटों के अभाव में बीपी, पेशाब, यूपीटी और एचबी जैसी मामूली जांच ही हो पाती है। डिस्पेंसरी को हर महीने नौ तारीख को नाम मात्र के जांच किट उपलब्ध करवाई जाती है। जो करीब एक सप्ताह में खत्म हो जाती है। इसके बाद मरीजों को जांच के लिए बीके अस्पताल का रास्ता दिखा दिया जाता है। बीके की प्रयोगशाला की हालत वैसे भी किसी से छुपी नहीं है।

ऐसा नहीं है कि डिस्पेंसरी में मरीज आते नहीं है। ओपीडी में हर रोज आसपास की झुग्गी बस्ती और कालोनियों से करीब सौ से सवा सौ मरीज हर रोज इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा डिस्पेंसरी में एक डिलीवरी हट भी है। डिस्पेंसरी की डाक्टर का दावा है कि यहां हर महीने करीब 50 से 70 महिलाओं की प्रसूति की जाती है।

डिस्पेंसरी में 24 घंटे प्रसूति की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तीन स्टाफ नर्सो को रहने के लिए भवन की दूसरी मंजिल में क्वार्टर दिए गए है। लेकिन यह स्टाफ नर्स अपनी सुरक्षा खतरे में डाल कर यहां रहने के लिए मजबूर हो रही है। क्योंकि डिस्पेंसरी में चौकीदार न होने के कारण डिस्पेंसरी की ओपीडी का समय खत्म होते ही यहां शराबियों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। कई बार ये नशेड़ी नर्सो के साथ अभद्र हरकत तक कर डालते हैं।

ऐसा नहीं है कि जिला के सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा को डिस्पेंसरी की हालत के बारे में पता नहीं है। लेकिन सबकुछ जानने के बावजूद उन्होंने आज तक इसकी हालत में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उनकी लापरवाही के कारण ही यहां आने वाले मरीजों को ओपीडी कार्ड तक उपलब्ध नहीं करवाए जाते। मरीजों को अपनी दवाईयां लिखवाने के लिए बाहर से पांच रुपये में कॉपी खरीद कर लानी पड़ती हैं।

डिस्पेंसरी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंर्तगत आती है। भाजपा विधायक मूलचंद चुनाव के दौरान इस गांव में वोट मांगने और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए तो दर्जनों बार आ चुके है। लेकिन उन्होंने कभी डिस्पेंसरी में झांक कर हालत के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया।

ईएसआई सेक्टर 8 : अपने इलाज की बाट जोहता एक अस्पताल

फ़रीदाबाद (म.मो.) बल्लबगढ क्षेत्र के करीब 4 लाख मज़दूर परिवारों के लिये बना 200 बेड का अस्पताल खुद अपने इलाज की बाट बरसों से जोह रहा है। ईएसआई निगम ने 200 बेड के लिये शानदार इमारत 1993 में बना कर हरियाणा सरकार को सौंप दी। लेकिन हरियाणा सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो या चौटालों की या फ़िर संघियों की, ने कभी अस्पताल की सुध नहीं ली।

इतनी भारी-भरकम इमारत में मात्र 50 बेड का अस्पताल ही शुरू किया जा सका है। इसके चलते पांच मंजिला इमारत के चार तल बिल्कुल खाली व शेष एक तल के भी कुछ ही भाग का इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल न होने की वजह से अच्छी-भली इमारत की हालत दिन-ब-दिन खस्ता होती जा रही है।

दिनांक 2 जनवरी को इस संवाददाता ने अस्पताल का अवलोकन किया तो पाया कि केवल 10 मरीज़ ही वहां भर्ती थे। वे भी नाम मात्र की बीमारियों के। कोई मरीज़ आये भी तो क्यों आये, भर्ती होने का जोखिम ले भी तो कैसे ? आंखों वाले विभाग में कोई डॉक्टर नहीं था, पूछने पर पता चला कि वे मेडिसिन विभाग में बैठे हैं। वहां जाकर देखा तो उनके साथ एक महिला डॉक्टर एनेस्थिसिया (बेहोशी) वाली भी बैठी मरीज़ों को देख रही थी।

मेडिसिन के असल डॉक्टर अनिल कुमार हैं जो वहां पर नहीं थे। करीब एक घंटे से 25 मरीज़ उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे। इधर-उधर से पूछने पर पता चला कि डॉक्टर साहब आये थे, 8-10 मरीज़ देखकर आपातकालीन विभाग में जा बैठे। वहां बैठ कर वे मरीज़ों को मैट्रो अस्पताल में रैफ़र करने का धंधा करते हैं। नियमानुसार वे साधारण बीमारी वाले को रैफ़र नहीं कर सकते, इसलिये वे उन्हें हृदय का रोगी तक बनाकर रैफ़र कर देते हैं। जाहिर है डॉ. अनिल मैट्रो के लिये मुफ़्त में तो यह धंधा करने वाले हैं नहीं।

संदर्भवश सुधी पाठकों को याद दिला दें कि ये वहीं डॉक्टर साहब हैं जिनका तबादला मैट्रो अस्पताल वालों ने तत्कालीन श्रम मन्त्री शिवचरण लाल शर्मा से कह कर गुड़गांव का करा दिया था, क्योंकि वे मरीजों को उनके यहां न भेज कर सर्वोदय अस्पताल में भेजते थे। अब मैट्रो वाले उन्हें, अपने प्रभाव से, इसी शर्त पर यहां फ़िर से वापस लायें हैं कि वे मैट्रो को, मरीज़ों के रूप में बिज़िनेस देंगे, अन्यथा पुन: तबादले के लिये तैयार रहें। विदित है कि एनेस्थिसिया डॉक्टर का काम ओटी (ऑपरेशन थियेटर) में सर्जरी डॉक्टर के साथ चलता है। अब चूंकि इस अस्पताल में ओ.टी को तो ताला मार रखा है, वहां किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसलिये एनेस्थिसिया डॉक्टर को उस मेडिसन विभाग में मरीज देखने को बैठा दिया जिसमें उनकी कोई महारत नहीं है। ऐसे में वे केवल मरीज़ों को बहलाने के लिये पर्ची पर कुछ भी दवा लिख कर वे अपनी ड्यूटी पूरी कर लेती हैं।

इसी तरह एक अन्य डॉक्टर माइक्रोबॉयलॉजी के विशेषज्ञ हैं। उन्हें भी हर रोज़ दंत विभाग को छोड़ कर किसी न किसी विभाग में मरीज़ों को देख कर टाइम पास करने को बैठा दिया जाता है। उनकी जिस विशेषज्ञता के लिये उन्हें रखा गया है, उसके लिये आवश्यक लैबोरेट्री एवं साजो-सामान ही यहां नहीं है। इसके अभाव में मरीज़ों के ब्लड आदि के नमूने लेकर जांच के लिये एनएच-3 वाले बड़े अस्पताल या प्राइवेट लैब को भेजे जाते हैं। इससे चंद घंटों में पूरी होने वाली जांच के परिणाम कई दिनों में आते हैं और तब तक मरीज़ों को इधर-उधर भटकना पड़ता है।

हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी यहां बहुत जरूरत है। डॉक्टर पुनित, जो एक विशेषज्ञ यहां हैं भी वे पदोन्नत होकर यहीं एमएस (मेडिकल सुपरिंटेंडेंट) हो गये हैं। अब एमएस होने के बाद वे सर्जरी का काम कैसे कर सकते हैं ? वे अपना दफ़्तर सम्भालें कि मरीज़ों को देखें। ऐसे में ओटी को ताला मार कर रैफ़र करने का ही काम बचता है, जो कोई भी कर सकता है।

डाक से 'मजदूर मोर्चा' मंगवाने वाले पाठकों के लिए सूचना

डाक द्वारा 'मज़दूर मोर्चा' प्राप्त करने वाले स्थानीय सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रति प्राप्त करने के लिये अपने हॉकर से सम्पर्क करें, क्योंकि 7 फरवरी से साप्ताहिक होने के पश्चात अखबार को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं हो पायेगा।

मरीज़ों की जान जोखिम में डाल कर बीके में की जाती है डायलिसिस

फ़रीदाबाद (म.मो.) आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार ने किडनी की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को निजी अस्पताल के हाथों लूटने से बचाने का दावा करते हुए बीके अस्पताल में पीपीपी (प्राइवेट पब्लिक पार्टरशीप) मोड पर एक डायलिसिस सेन्टर खोलने की अनुमति दी थी। वैसे तो इस सेन्टर का अभी तक उद्घाटन तक नहीं हुआ है लेकिन यह पिछले करीब छह महीने से गैरकानूनी तरीके से यह चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक जिले में किडनी रोगों से पीड़ित हजारों की संख्यां में मरीज मौजूद है। इन मरीज़ों को डायलिसिस करवाने के लिए निजी अस्पतालों के हाथों लुटने पर मजबूर होना पड़ता है। इस तरह के मरीजों के 'फायदे' के लिए सरकार ने बीके अस्पताल में पीपीपी मोड पर डायलिसिस सेन्टर खोलने की घोषणा की थी। सेन्टर को चलाने का ठेका बेशक डीसीडीसी कंपनी को दिया गया है लेकिन इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी बीके अस्पताल की है। इस सेन्टर को शुरू करने के लिए इस कंपनी को बीके अस्पताल की तरफ दूसरी मंजिल में जगह भी दे दी गई। जहां पर कंपनी ने डायलिसिस की आठ मशीने लगा कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन कंपनी ने सेन्टर में अन्य आवश्यक संसाधन आज तक जुटाने की जरूरत महसूस नहीं की। जानकार सूत्रों के मुताबिक डायलिसिस सेन्टर में इन मशीनों के साथ ओपीडी और एक माइनर ऑपरेशन थियेटर हर हाल में होना चाहिए। लेकिन इस सेन्टर में इन दोनों में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सेन्टर में एक विशेषज्ञ डाक्टर और एक एमडी फिजिशियन डाक्टर भी हर समय मौजूद रहना चाहिए। लेकिन बीके अस्पताल का यह सेन्टर सिर्फ चार तकनीशियनों के भरोसे चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक जिला स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉ. संजीव भगत को इस सेन्टर में तैनात करने के उदेश्य से सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर पीजीआई रोहतक में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था। डॉ. भगत को छह महीने का प्रशिक्षण लेने के बाद लौट कर आए करीब छह महीने का समय बीत चुका है। लेकिन आज तक सीएमओ डॉ. अरोड़ा ने उन्हें सेन्टर में तैनात करने की जरूरत महसूस नहीं की। जिला सिविल सर्जन डॉ. गुलशन अरोड़ा ने तुगलकी कारनामा करते हुए डॉ. संजीव भगत को संजय कालोनी की डिस्पेंसरी में तैनात किया हुआ है जहां उनका कोई काम नहीं है। जबकि डिस्पेंसरी में डॉ. भगत के अलावा तीन डाक्टर पहले से ही मौजूद है।

डीसीडीसी कंपनी और जिला स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से इस सेन्टर को चला रहा उससे कभी भी यहां डायलिसिस करवाने के लिए आने वाले मरीजों की जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। डायलिसिस करवाने के लिए आने वाले मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में डायलिसिस के दौरान किसी मरीज की जान चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी न तो कंपनी लेगी और न ही बीके अस्पताल।

सेन्टर को औपचारिक रूप से शुरू करवाने के काम को सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा जानबूझ कर लटकाए रखना चाहते हैं। क्योंकि वे चाहते ही नहीं हैं कि यह सेन्टर सही तरीके से चले। सेन्टर में मात्र 1200 रुपये की दर पर डायलिसिस की जाती है। जबकि निजी अस्पताल डायलिसिस करने के बदले में मरीजों से हजारों रुपये वसूलते हैं। यदि बीके अस्पताल का सेन्टर सही तरीके से शुरू हो गया तो निजी अस्पतालों की दुकान बंद हो जाएगी और वे सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा की सेवा पानी करना बंद कर देंगे।

खुद को गरीबों की हमदर्द बता कर चुनाव जीत कर इस इलाके से विधायक बनी सीमा त्रिखा, जो आए दिन बीके अस्पताल में नौटंकी करने तो पहुंच जाती हैं, लेकिन यहां तैनात अधिकारियों की लगाम कसने की कभी कोशिश नहीं की।